

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तरांचल, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग :1

देहरादून: दिनांक: 04 अगस्त, 2006

विषय:- महाधिवक्ता कार्यालय हेतु सृजित पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल शासनादेश संख्या-237/न्याय अनुभाग/2001, दिनांक 25-06-2001 द्वारा सृजित विभिन्न श्रेणी के 38 पदों, शासनादेश संख्या-3-एक(6)/न्याय विभाग/2003, दिनांक 23-01-2003 द्वारा सृजित विभिन्न श्रेणी के 17 पदों, शासनादेश संख्या-7एक(6)/न्याय विभाग/2003, दिनांक 22-07-2003 द्वारा सृजित 01 पद एवं शासनादेश संख्या 10-एक(6)/न्याय विभाग/2004, दिनांक 06-08-2004 द्वारा सृजित 04 पद अर्थात् कुल 60 पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायें, दिनांक 01-03-2006 से 28-02-2007 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त के साथ इस हेतु स्वीकृत कार्यालय व्यय के अनुदान की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2- उक्त कार्यालय के पदधारण करने वाले कर्मचारियों की निरन्तर नियुक्ति भी शासन के अग्रिम आदेशों तक स्वीकृत की जाती है ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता(काउन्सिल)-03-महाधिवक्ता-00" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश उ0 प्र0 शासन के वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20-07-88 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-870/दस-92-24(8)/92, दिनांक 07-11-92 जो उत्तरांचल राज्य में भी अनुकूलित है, द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं ।

भवदीया

(इन्दिरा आशीष)
सचिव न्याय ।

संख्या- 383 /XXXVI(1)/2006- तददिनेंक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।

3- वित्त अनुभाग-5/एन.आई.सी./गार्ड बुक ।

आज्ञा से
(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।